



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 229]
No. 229]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 14, 1990/भाद्र 23, 1912
NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 14, 1990/BHADRA 23, 1912

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

मंत्रिमंडल सचिवालय

नई दिल्ली, 24 अगस्त, 1990

संकल्प

सं० 50/4/18/88-टी०एस० -सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा के सभी पहलुओं पर समन्वित एवं व्यापक ढंग से विचार करने के लिए एक राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् गठित करने की अपनी इच्छा की घोषणा की थी। यह परिषद् विदेशी, आर्थिक, राजनीतिक तथा सैन्य स्थितियों और हमारी घरेलू चिन्ताओं एवं उद्देश्यों से उनके संबंधों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों पर सम्पूर्ण दृष्टिकोण अपनायेगी।

2. चूंकि बाह्य भौगोलिक सामरिक महत्व का वातावरण तथा क्षेत्र की अंतराष्ट्रिक परिस्थिति दोनों ही तेजी से बदल रहे हैं, इसलिए सम्पूर्ण दृष्टिकोण की आवश्यकता का आज विशेष महत्व है। अन्तर्राष्ट्रीय वातावरण में राष्ट्रीय परिवर्तन हुए हैं जिससे संसार के विभिन्न क्षेत्रों में अनिवार्य रूप से प्रवृत्त के नये संतुलन की स्थापना को बढ़ावा मिलेगा। आर्थिक सोच विचार द्वारा ज्यादातर अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक गतिविधियां निर्धारित की जा रही हैं। अनेक स्थिति भी बदल रही हैं और बहुत से क्षेत्रों में सामाजिक तथा प्रशासनिक ढांचे पर दबाव है। देश के कुछ भागों में ये प्रवृत्तियां बाहरी ताकतों द्वारा संयोजित की जाती

हैं जो उग्रवादी तथा आतंकवादी संगठनों को उनकी गैर-कानूनी एवं ध्वंसात्मक गतिविधियों में मदद देती हैं एवं बढ़ावा देती हैं। अगर इन प्रवृत्तियों को बगैर रोक-टोक के जारी रहने दिया जाता है, तो ये राष्ट्र की एकता एवं अखण्डता को क्षति पहुंचा सकती हैं।

3. अतः सरकार ने एक राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् गठित करने का निर्णय लिया है जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति शामिल होंगे :-

प्रधानमंत्री —अध्यक्ष

रक्षा मंत्री —सदस्य

वित्त मंत्री —सदस्य

गृह मंत्री —सदस्य

विदेश मंत्री —सदस्य

यह परिषद् आवश्यकतानुसार अन्य केन्द्रीय मंत्रियों तथा किसी राज्य के मुख्य मंत्री को परिषद् की बैठकों में भाग लेने के लिए अनुरोध कर सकती है। यह परिषद् आवश्यकतानुसार सुविधों और विशेषज्ञों को भी इसकी बैठकों में भाग लेने के लिए आमंत्रित कर सकती है।

4. राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् का मुख्य प्रयास होगा राजनीतिक, सैनिक तथा आर्थिक क्षेत्रों में उत्पन्न हो रही बाह्य स्थिति तथा हमारा आंतराष्ट्रिक स्थिति के बीच सम्बंधों को ध्यान में रखते हुए नीति निर्माण के प्रति

सम्पूर्ण दृष्टिकोण विकसित करना, क्योंकि इसका राष्ट्रीय सुरक्षा पर असर पड़ता है। इससे उन रणनीतियों की पहचान होगी जो रक्षा, आंतरिक सुरक्षा तथा विदेशी मामलों में हमारे प्रयासों के अच्छे परिणाम निकालने की आशा बहाली है। यह परिपद हम बात का अनिवार्य करेगी कि आंतरिक तथा भौगोलिक सामरिक महत्व के वातावरण का मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन मूल्यांकन हो, जिससे कि संबंधित मामलों में सरकार नीति बनाने में परिप्रेक्ष्य का काम करे। परिपद के विचार के लिए जो विषय प्रस्तुत किए जा रहे हैं वे मोटे तौर पर निम्नलिखित को शामिल करेंगे :—

(क) बाह्य खतरे की स्थिति।

(ख) सामरिक महत्व की रक्षा संबंधी नीतियां।

(ग) अन्य सुरक्षा संबंधी खतरे, विशेष रूप से ऐसे खतरे जिनका संबंध परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष तथा उच्च टेक्नालाजी से है।

(घ) आन्तरिक सुरक्षा जिसमें प्रति-विद्रोह, प्रति-आतंकवाद और अभि-आतंकता जैसे पक्ष शामिल हैं।

(ङ) देश के भीतर ऐसे उत्पादी का संभावना होना, विशेष रूप से जिसका सामाजिक, सांप्रदायिक अथवा प्रादेशिक आयाम हो।

(च) भारत की आर्थिक तथा विदेशी नीतियों पर विश्व अर्थव्यवस्था में उत्पन्न हो रही प्रवृत्तियों की सुरक्षा संबंधी उत्पन्न।

(छ) उर्जा, खाद्य तथा वस्त्र जैसे क्षेत्रों में बाह्य आर्थिक खतरे।

(ज) नक्करी तथा हथियारों, इत्यों तथा नाकॉटिक के अवैध व्यापार जैसे सीमापार अपराधों से उत्पन्न खतरे।

(झ) सामरिक महत्व के तथा सुरक्षा संबंधी मामलों पर राष्ट्रीय महामति तैयार करना।

5. राष्ट्रीय सुरक्षा परिपद को स्ट्रैटजिक कोर ग्रुपों या गठनों द्वारा चलाया जाएगा जिसमें सचिव, मंत्रिमंडल अध्यक्ष होंगे और दोनों सेवाओं के प्रतिनिधि तथा संबंधित मंत्रालय होंगे। स्ट्रैटजिक कोर ग्रुप, राष्ट्रीय सुरक्षा परिपद को मंत्रालयों या अन्य सरकारों एजेंसियों या विशेष टास्क फोर्स द्वारा जैसे कि पैरा 6 में दर्शाया गया है प्रस्तुत किए गए कार्यों को और रिपोर्टों के समुचित अध्ययन का निरीक्षण करेगा।

6. राष्ट्रीय सुरक्षा परिपद का अपना एक अलग सचिवालय होगा जिसका प्रमुख सचिव होगा और वह अधिकार भारत सरकार के सचिव के समकक्ष होगा। यह सचिवालय स्ट्रैटजिक कोर ग्रुप को भी सेवाएं प्रदान करेगा।

7. राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित विभिन्न पहलुओं के गहन अध्ययन हेतु, परिपद के अध्यक्ष जितनी चाहें उतनी टास्क फोर्स स्थापित कर सकते हैं। प्रत्येक टास्क फोर्स विशेष क्षेत्र की सुरक्षा से संबंधित होगी और उसके सदस्य सरकारी सुरक्षा मामलों में कार्यरत मंत्रालयों और एजेंसियों से ही लिए जाएंगे। प्रत्येक टास्क फोर्स का प्रमुख उस टास्क फोर्स को सौंपे गए कार्य का अच्छा ज्ञान और अनुभव रखता होगा। यद्यपि टास्क फोर्स प्रशासनिक तौर पर राष्ट्रीय सुरक्षा परिपद के सचिवालय में जुड़ा रहेगा, किन्तु सरकारी या बाहरी एजेंसियों से विशेषज्ञ सहायता के लिए अनुरोध कर सकता है।

8. राष्ट्रीय सुरक्षा परिपद, राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर देश के भीतर अधिक से अधिक सभायित संवेगशीलता को बहाल देने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण राष्ट्रीय सुरक्षा समस्याओं पर सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने के लिए भी प्रयत्न करेगी। इसके लिए एक राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का गठन किया जाएगा जिसके सदस्यों की मुख्य-मंत्रियों, मसद सदस्यों, विद्वानों, वैज्ञानिकों प्रशासन सेवा का अच्छा अनुभव रखने वाले व्यक्तियों, सशस्त्र बलों, प्रेस और समाचार माध्यमों

शामिल किए जाएंगे। बोर्ड की एक वर्ष में कम से कम दो बार बैठक होगी और यह अपनी कार्यवाहियों का रिकार्ड रखेगा।

बोर्ड, राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों पर विचारों एवं विकल्पों का एक व्यापक क्षेत्र प्राप्त करने के लिए आवश्यक रूप से एक रचनात्मक संस्था में कार्य करेगा। यह राष्ट्रीय सुरक्षा परिपद पर विचार के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले कार्यों एवं उनके अध्ययन कार्य में महत्वपूर्ण योगदान का कार्य करेगा। बोर्ड को राष्ट्रीय सुरक्षा परिपद के सचिवालय की सेवाएं प्राप्त होंगी।

विनोद चन्द्र पाण्डे, मंत्रिमंडल सचिव

CABINET SECRETARIAT

New Delhi, the 24th August, 1990

RESOLUTION

No. 50/4/18/88-TS.—The Government had announced their intention to set up a National Security Council to consider all aspects of national security in a coordinated and comprehensive manner. The Council will take a holistic view of national security issues in the light of the external, economic, political and military situations and their linkages with our domestic concerns and objectives.

2. The need for a holistic approach is especially important today as both the external geo-strategic environment and the internal situation in the country are changing rapidly. The international environment has undergone dramatic changes which will inevitable lead to the establishment of new equilibria of power in different regions of the globe. Economic considerations are increasingly determining international political dynamics. The domestic situation is also changing and in many regions, the social fabric and the administrative structure is under strain. In some parts of the country, these strains are compounded by external forces aiding and abetting militant and terrorist groups in their unlawful and subversive activities. These trends if allowed to go unchecked, could undermine the nation's integrity and unity.

3. Government have, therefore, decided to set up a National Security Council comprising the following

Prime Minister : Chairman

Minister of Defence : Member

Minister of Finance : Member

Minister of Home Affairs : Member

Minister of External Affairs : Member

The Council may, as necessary, request other Union Ministers and any Chief Minister of a State to attend meetings of the Council. The Council may also invite experts and specialists to attend its meetings as necessary.

4. The main endeavour of the National Security Council will be to evolve an integrated approach to policy making as it affects national security, taking account of the linkages between the evolving external situation in the political, Military and economic fields and our domestic situation. This should lead to the identification of strategies which optimise our efforts in defence, internal security and foreign affairs. The council will ensure that medium-term and long-term assessments are made of the internal and geo-strategic environment to serve as a perspective for shaping Government policy in related matters. The subjects submitted for the consideration of the Council will broadly cover the following:

(a) external threat scenario;

(b) strategic defence policies;

(c) other security threats specially those involving atomic energy, space and high technology;

- (d) internal security covering aspects such as counter-insurgency, counter-terrorism and counter-intelligence;
- (e) patterns of alienation likely to emerge within the country, especially those with a social, communal or regional dimension;
- (f) security implications of evolving trends in the world economy on India's economic and foreign policies;
- (g) external economic threats in areas such as energy, commerce, food and finance;
- (h) threats posed by trans-border crimes such as smuggling and traffic in arms, drugs and narcotics;
- (i) evolving a national consensus on strategic and security issues.

5. The National Security Council shall be assisted by a Strategic Core Group comprising the Cabinet Secretary as Chairman and representatives of the three Services and the Ministries concerned. The Strategic Core Group will supervise the submission of appropriate studies, papers and reports to the National Security Council from the Ministries or other agencies of the Government, or from Special Task Forces as indicated in para 7.

6. The National Security Council will have a separate Secretariat which will be headed by a Secretary who will be an officer in the rank of Secretary to the Government of India. This Secretariat will also service the Strategic Core Group.

7. For in-depth study of different aspects concerning national security, Task Forces may be established as may be decided by the Chairman of the Council. Each Task Force will be concerned with specific areas of security and its membership will be drawn from the Ministries and agencies dealing with the security issues within the Government. Each Task Force will be headed by an experienced person well-versed in matters assigned to that Task Force. While the Task Forces will be administratively attached to the Secretariat of the National Security Council, they may request for expert assistance from agencies within or outside the Government.

8. The National Security Council will also oversee efforts to increase public awareness on important national security problems with a view to promoting the widest possible consensus within the country on issues affecting the nation's security. Towards this end, a National Security Advisory Board will be constituted comprising members drawn from among Chief Ministers, Members of Parliament, academics, scientists and persons having rich experience of service in the administration, armed forces, press and the media. The Board will meet at least twice a year and keep a record of its proceedings. The Board will essentially serve as a mechanism for obtaining a broad range of informed views and options on national security issues. This will form an important input into studies and papers submitted for the consideration of the National Security Council. The Board will be serviced by the Secretariat of the National Security Council.

V. C. PANDE, Cabinet Secy

